







# संपादकीय

अमेरिकी धमकी से पहले भी भारत पर हुआ है बड़ा ग्रेमाव, रुस से कच्चा तेल खरीदना अब हो सकता है मुश्किल



अमेरिका की नई धमकी से भारत की चिंता जरूर कुछ बढ़ गई है, क्योंकि सचमुच अगर वह ऐसा करता है, तो भारत की तेल कंपनियों के लिए रूस से तेल खरीदना मुश्किल हो जाएगा। अभी भारत सबसे अधिक कच्चा तेल रूस से खरीदता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद विश्व राजनीति में धमकी की नई परंपरा कायम करने पर तुले हैं। अब उन्होंने रूस से कच्चा तेल खरीदने वालों को धमकाया है कि जो ऐसा करेगा, वह अमेरिका में कारोबार नहीं कर पाएगा। ऐसे देशों पर पच्चीस से पचास फौसद तक अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। यह धमकी उन्होंने इसलिए दी है कि रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की दिशा में न तो रूस और न ही यूक्रेन ने अपेक्षित सहयोग का रुख दिखाया है। इससे ट्रंप निराश है। पिछले महीने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को बुला कर ट्रंप ने कड़े शब्दों में फटकार लगाई थी। यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगा दी गई है। इससे उम्मीद बनी थी कि रूस, अमेरिका की युद्ध विराम संबंधी शर्त मान जाएगा, मगर उसने अपनी शर्त रख दी कि सभी नाटो देश यूक्रेन को सैन्य मदद और गोपनीय सूचनाओं पर रोक लगाएं, तभी वह युद्ध विराम पर विचार कर सकता है। यह अमेरिका के लिए कठिन ही नहीं, शायद कभी पूरी न हो सकने वाली शर्त है। ऐसे में ट्रंप ने अब रूस पर नकेल कसने का रास्ता चुना है। मगर यह रास्ता भी उनके लिए कितना आसान और कारगर साबित होगा, कहना मुश्किल है। अमेरिका की नई धमकी से भारत की चिंता जरूर कुछ बढ़ गई है, क्योंकि सचमुच अगर वह ऐसा करता है, तो भारत की तेल कंपनियों के लिए रूस से तेल खरीदना मुश्किल हो जाएगा। अभी भारत सबसे अधिक कच्चा तेल रूस से खरीदता है पहले ईरान और खाड़ी देशों से खरीदता था, मगर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद भारतीय तेल कंपनियों ने वहाँ से तेल खरीदना बंद करके रूस से खरीदना शुरू कर दिया था। इस तरह कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से महांगी तेजी से बढ़ेंगी, जिसका अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हालांकि भारतीय तेल कंपनियां अभी समझ नहीं पा रही हैं कि अमेरिका का अतिरिक्त शुल्क लगाने का ढांचा क्या होगा, इसलिए वे इसे अधिक चिंता का विषय नहीं मान रही हैं, परंतु जिस तरह पहले ही पारस्परिक शुल्क नीति के तहत अमेरिका ने भारी शुल्क थोप दिए हैं, उससे भारत के लिए संतुलन बिठाना कठिन हो रहा है। यह नया शुल्क और परेशान करने वाला साबित हो सकता है। मगर ट्रंप प्रशासन के लिए भी अपनी शुल्क नीति पर लंबे समय तक कायम रह पाना कठिन होगा। इसे लेकर अमेरिका में ही विरोध हो रहा है। इसलिए कि पारस्परिक शुल्क के चलते अमेरिकी कारोबार पर भी बुरा असर पड़ सकता है। जिन चीजों के लिए अमेरिका दूसरे देशों पर निर्भर है, उनकी कीमतें बढ़ेंगी, तो वहाँ भी महांगी बढ़ेंगी। ऐसे में अमेरिकी लोगों का विरोध लंबे समय तक सहन कर पाना ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा। वहाँ के मध्यावधि चुनाव में ट्रंप की पार्टी के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिर यह भी कि ट्रंप के नए एलान से रूस कितने दबाव में आ पाएगा, कहना मुश्किल है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ जैसा व्यवहार ट्रंप ने किया, उससे ज्यादातर पश्चिमी देश नाराज हैं। इसलिए रूस-यूक्रेन संघर्ष रुकवाने का उनका दावा कमज़ोर पड़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच चल रहा संघर्ष निश्चित रूप से रुकना चाहिए, यह दुनिया की बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है। मगर धौंस और धमकी के सहरे ऐसा हो पाना शायद ही संभव हो, इसके और उलझने की आशंका बनी रहेगी।

गांव शब्द आते ही  
हम और आप खेतों,  
किसानों, ग्रामीण

माहिलाओं, और  
गलियों में खेलते  
बच्चों की कल्पना  
करने लग जाते हैं।

हालांकि अब गाव  
भी वैसे नहीं रहे जैसे  
कि हमारी कल्पनाओं  
में अब तक रहे हैं।  
ग्रामीण इलाकों में

जिस तरह  
सामाजिक और  
आर्थिक जटिलताएं  
रही हैं, उसके  
मद्देनजर देखें तो  
कुछ मायानों में यह  
काफी अच्छा है कि  
हमारे गांव आज की  
दुनिया से जुड़ रहे हैं।

# बदलाव के दौर में गांवों के अस्तित्व का संकट, शहरी संस्कृति की तरफ बेतहशा दौड़ रहे लोग

भल हो शहर के निराए के कमरा मध्याटा-  
सी घुटन भरी जगह में रहना पड़े, सिर्फ शहर में  
रहने के लिए लोग मजबूरीवश खुला आकाश  
भूल जाते हैं। छोटी-छोटी चीजों के लिए संघर्ष  
करना उनकी दिनचर्या का भाग बन जाता है।  
लेकिन जब कुछ लोग अपने बच्चों को शहर दे  
पाते हैं तब भी वे गांव वापस लौटना पसंद नहीं  
करते हैं।

गांव शब्द आते ही हम और आप खेतों, किसानों, ग्रामीण महिलाओं, और गलियों में खेलते बच्चों की कल्पना करने लग जाते हैं। हालांकि अब गांव भी वैसे नहीं रहे जैसे कि हमारी कल्पनाओं में अब तक रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में जिस तरह सामाजिक और आर्थिक जटिलताएं रही हैं, उसके मद्देनजर देखें तो कुछ मायनों में यह काफी अच्छा है कि हमारे गांव आज की दुनिया से जुड़ रहे हैं। आज की दुनिया तकनीक और प्रचार पर चलती है। गांव के लोग भी समझ रहे हैं कि अगर दुनिया में टिके रहना है तो हमें इन सभी चीजों को अपनाना होगा।

मगर इस क्रम में जो दिशा अपनाई गई है और जो रफतार है, इससे जो समझ विकसित और मजबूत हो रही है, उसने गांव को गांव से दूर कर दिया है। जहां गांव की सलताएं शहरों में पहुँचनी चाहिए थी, वहां शहर गांवों तक पहुँच गए हैं। इमारतें बन गईं, खेत कट गए, जंगलों का हाल बेहाल हो गया। यहां तक कि दूरदराज के गांवों की देश यह होती गई है कि वे खाली होते जा रहे हैं। इसके अलावा, गांव की सरलता और सहजता अब धीरे-धीरे गयब होती दिखने लगी है। गांव जिस तरह शहरों से जुड़ रहे हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन इस क्रम में जो चीजें पीछे छूट गई या जो लोग पिछड़ गए, उनका अस्तित्व संकट में पड़ गया है। वे गांव कई-कई स्तर पर खाली हो गए, क्योंकि उनके बाशिदे रोजगार, नई दुनिया की तलाश, बाबरी के माहौल और अपने भीतर के गांव को निकालने शहर आ गए। शहर में बसने का एक मुख्य कारण शिक्षा भी रहा। शिक्षा, रोजगार, नौकरी, पैसा, शोहरत सभी शहर में हैं, तो फिर प्रश्न है कि गांव का क्या होगा? गांव को किसने इस हाल में छोड़ दिया कि लगातार 'अहा ग्राम्य जीवन' के राग और महिमांडन के बीच गांव लाचार होते चले गए? आज भी ऐसे गांवों को देखा जा सकता है



लोगों ने वहां बड़े-बड़े आशियाने बसाए, लेकिन अब वहां सिर्फ पक्षी बैठते हैं। उन घरों को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें मेहनत और आशा के साथ बनाया गया था, लेकिन उन सब पर शहर हावी हो गया और गांव पीछे छूट गया। ऐसे तमाम लोग हैं, जिनके भीतर अपने कुछ मित्रों, रिश्तेदारों का शहरी जीवन देखकर घर के प्रति लगाव कर्मजार पड़ गया और वे शहरी संस्कृति की तरफ बेतहशा दौड़ने लगे। इनके मूल में एक वजह यह भी है कि गांव में रोजगार की कमी है। सरकारें आईं और गईं। योजनाएं भी लाईं गईं और उन्हें कार्यान्वित करने की कोशिश आज भी जारी है, लेकिन छोटे-मोटे कामों, इंसानी और छोटे कारोबारियों के अतिरिक्त अधिकतर गांवों की दशा ठीक नहीं है। ऐसे में मजबूर परिवार गांव छोड़ देते हैं। किसी के गांव से शहर चले जाने पर कई बार सवाल तो उठाया जाता है, लेकिन शहर का रुख करने की वजहों पर शायद गौर नहीं किया जाता। जो लोग गांव में जीवन के जीवंत अनुभवों के साथ जीते हैं, उनके सामने आखिर कैसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि वे गांव छोड़ कर बाहर निकल जाते हैं? भले ही शहर के किराए के कमरों में छोटी-सी घुटन भरी जगह में रहना पड़े, सिर्फ शहर में रहने के लिए लोग मजबूरीवश खुला आकाश भूल जाते हैं। छोटी-छोटी चीजों के लिए संघर्ष करना उनकी दिनचर्या का भाग बन जाता है। लेकिन जब कुछ लोग अपने बच्चों को शहर दे पाते हैं तब भी वे गांव वापस लौटना पसंद नहीं करते हैं। शहर उनकी आस बन जाता है और गांव उनका इतिहास हो जाता है। वे अब कभी नहीं लौटना चाहते उन घरों में जिनमें वे कभी बहुत खुश रहते थे और खुले गलियारों में जहां उन्हें सांस लेने के लिए सुदूर हवा मिलती थी। ऐसा क्यों हुआ? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन शहरों का भी कम बुरा हाल नहीं है। भीड़ बढ़ने से शहरों की स्थिति बहुत खराब हो गई गई है। शहर में प्रदूषित हवा, अस्वच्छता, कंक्रीट की इमारतें, वृक्षविहीन सड़कें, बाहरों का शोर, मनुष्य की टकराहट और भावनाओं के अवेग का प्रदूषण है। इसे चाहकर भी मिटाना संभव नहीं है। ऐसे में क्या किया जाए? क्यों न गांव के खालीपन को भरा जाए और वहां भी शहर जैसा विकास किया जाए, ताकि लोग गांव छोड़कर न जाएं? रोजगार, शिक्षा, कारोबार, तकनीक नई दुनिया से गांव का परिचय करवाकर ऐसा संभव हो सकता है। फिर लोग लौटने लगेंगे अपने खाली पड़े आशियानों में, खेतों में रैनक होगी, जंगल फिर बढ़ेंगे, शहर भी सांस लेने लगेंगे और सब ठीक होने लग जाएगा। शहर और गांव अलग-अलग होंगे, पर कदम-ताल मिला सकेंगे। गांव के बच्चे भी शहर के बच्चों की तरह पढ़ सकेंगे, तकनीकों से अवगत हो सकेंगे। गांव का सूनापन भर उठेगा, आंगन खिल उठेगा, वही शहर का शोर-शाबा थोड़ी राहत देगा और कोलाहल शांति में तब्दील हो जाएगा। शहर स्वच्छ और सुंदर बनेंगे, गांव न केवल खेती, बल्कि हर क्षेत्र में आगे होंगे, इसके लिए दोनों ही व्यवस्थाओं को संरक्षित करने का प्रयास करना होगा। न केवल सरकार को, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर हम सबका कर्तव्य है कि गांव और शहर की व्यवस्था को सही रूप में लाएं। इसी में राष्ट्र का विकास निहित है। ये ही हमारे राष्ट्र को गांव की संस्कृति की तरफ लेकर चलेगा, जिसमें प्रेम, करुणा, संवेदना, कल्याण और मानवीय हित निहित होंगा।

## जम्मू-कश्मीर में दम तोड़ता अलगाववाद, बढ़ने लगी पाकिस्तान की मुश्किलें

द्विपक्षाय सबधां को दृष्ट से भी देखें तो पाकिस्तान को दबाव में बनाए रखने और अधिक भाव न देने की नीति इस अर्थ में भी कारगर रही कि सीमा पर हिंसक घटनाएं कम हुई हैं। वर्ष 2020 में चीन द्वारा पूर्वी लद्धाख में सैन्य मोर्चा खोलने के समय भी पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर कोई आक्रमक मुद्रा नहीं अपनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में संसद को एक सुखद सूचना दी। उहोंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी संगठन हुरियत कांफेस के कुछ धंडों ने भारत के प्रति निष्ठावान रहन का निर्णय किया है। इन गुटों में कश्मीर के सबसे कद्रुपंथी और पाकिस्तानपरस्त समझे वाले नेता सैयद अली शाह गिलानी के राजनीतिक उत्तराधिकारी मोहम्मद शफी की पार्टी डेमोक्रेटिक पीपुल्स मूवमेंट भी शामिल है। यह परिवर्तन दर्शाता है कि कश्मीर के कद्रुपंथी अलगाववादी इस्लामिक गुटों पर अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद से

होने वाले इस का है। कि वाले आ नाए त को यह बाली है। दों में कि हैं। नरम की परंतु मिल होने की बात नहीं करते थे। मनमोहन सरकार ने कभी यह सोचा ही नहीं कश्मीर की आजादी कभी संभव न हो सकती, क्योंकि भारत से अलग होते ही पाकिस्तान बलात उस पक्ष्या कर लेगा। नरम अलगावक को हवा देने वाली मनमोहन सरकार की इस विवेकशून्य नेतृत्व के द्वारा यासीन मलिक तक आ गए थे। यासीन मलिक वही दुर्दृष्ट आतंकी था, जिसका हथ वायु सेना अधिकारियों के खून सने थे। उस दौर में ऐसे आतंकी व प्रधानमंत्री आवास पर मेहमानवाद की जाती थी। जब भारत सरकार हुर्रियत के अलगाववादी नेताओं के कश्मीर पर चर्चा के लिए बुलाकर उनकश्मीरियों के प्रतिनिधि के रूप मायता देती थी तो पाकिस्तान द्विपक्षीय वार्ता में हुर्रियत को पक्ष बना

बढ़ने लगी पा के प्रति निष्ठा पड़ रही हैं। कि दशकों को लेकर अ कश्मीर में किया था। सरकारों की तुलनात्मक बार-बार भार के बावजूद प की जाती थी कहीं मानती यह क्षमता जिहादी आतं चाहे कश्मीर है। लिहाजा आवश्यक है था कि द्विप कुछ समय

त्तान की मुश्किल की मेज पर दबाव बना हासिल करने के लिए आतंकी हमले कराता था। दशकों से अनवरत चल रहा सरकार ने उड़ी आतंकी हमले से इसके ठीक विपरीत नीचे हुए पाकिस्तान से केवल दो बद नहीं की, बल्कि सर्जिंच और एयर स्ट्राइक जैसे विमानों से भी परहेज नहीं किया नहीं भारत ने पाकिस्तान की हौवे की हेकड़ी भी निकाली। पाकिस्तान से वार्ता बंद दूसरा लाभ यह हुआ कि भारत-पाकिस्तान का नाम जोड़ने की कूटनीतिक लगभग समाप्त हो चुकी। पाकिस्तान भारत का साथी रहा। अंतरराष्ट्रीय पटल पर

नाम अब चान और रूस जेस शक्तिशाली देशों के साथ लिया जाता है। द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से भी देखें तो पाकिस्तान को दबाव में बनाए रखने और अधिक भाव न देने की नीति इस अर्थ में भी कारगर रही कि सीमा पर हिंसक घटनाएं कम हुई हैं। वर्ष 2020 में चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख भूमि में सैन्य मोर्चा खोलने के समय भी पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर कोई आक्रामक मुद्रा नहीं अपनाई। उलटे इस तनाव के बीच ही फरवरी 2021 में उसने भारत के साथ नियंत्रण रेखा को लेकर संघविभाग की घोषणा कर दी, जो अभी तक जारी है। चूंकि पाकिस्तान अब भारत को लेकर अपनी जनता का ध्यान भटकाने में सक्षम नहीं रहा, इसलिए वहां आप जन का ध्यान अब घरेलू मुद्दों की ओर जाने लगा है। आंतरिक मोर्चे पर सशस्त्र अलगाववाद एवं गंभीर असंतोष ने भी पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

# वक्फ पर फैसले का वक्त, लोकसभा में पेश किए जाने की तैयारी

वर्क संशोधन  
विधेयक को  
लोकसभा में पेश किए  
जाने की सरकार की  
तैयारी पर विपक्षी दलों  
के अतार्किक रवैये को  
देखते हुए इस नतीजे  
पर पहुंचने के अलावा  
और कोई उपाय नहीं  
कि उसने अंधविरोध  
का रास्ता अपना लिया  
है। सभी इससे

व्यवहार तुष्टीकरण और वोट बैंक की क्षमता राजनीति का ही परिचायक है। इसके राजनीति के चलते वे कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ इस दुष्प्रचार को हवा देने में लगे हुए हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य मस्जिदों, मदरसों आदि की जमीन पर कब्जा करना है।

विपक्षी नेता यह देखने से भी सापेक्ष इन्कार कर रहे हैं कि किस तरह अनेक मुस्लिम संगठन वक्फ बोर्डों के कामकाज में सुधार की आवश्यकता जाता रहे हैं। विपक्षी की ओर से दिया जा रहा यह तर्क हास्यास्पद ही है कि मौजूदा वक्फ कानून में किसी तरह का संशोधन नहीं हो सकता। आखिर जब इस कानून में पहले भी संशोधन होते रहे,

यह तय है कि  
नदारी, पारदर्शिता  
जवाबदेही के बिना  
हीं ही सुशासन की  
उम्मीद नहीं की जा  
सकती। अगर कोई  
धिकारी आदेश के  
अनुपालन में  
परवाही बरतता है,  
तो उसके खिलाफ  
देह कार्रवाई होनी  
चाहिए। संसद की  
यी समिति का यह  
मुझाव उचित है कि  
संपत्ति का ब्योरा

संसदीय समिति के आदेश के बावजूद अधिकारियों ने नहीं दिया अचल संपत्ति का ब्योरा, उनके कार्यशैली पर सवाल उठना स्वाभाविक

ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना कहीं भी सुशासन की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर कोई अधिकारी आदेश के अनुपालन में लापरवाही बरतता है, तो उसके खिलाफ निस्संदेह कार्रवाइ होनी चाहिए। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देने के लिए बार-बार कहने पर भी सार्थक नतीजे नहीं निकलते हैं, तो इसकी वजह क्या हो सकती है, इसे समझा जा सकता है। दरअसल, कोई बड़ी दंडात्मक कार्रवाइ न होने से प्रायः अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्योरा देने से कतराते हैं। ऐसे में, संसद की एक स्थायी समिति ने निर्धारित समय सीमा में ब्योरा अचल संपत्ति की जानकारी देने से क्यों गुरेज? वे कुछ छिपा रहे हैं, तो कहीं न कि संपत्ति का ब्योरा दाखिल करने के

A wide-angle photograph of the National Assembly of Pakistan's lower house, the National Assembly. The room is filled with rows of wooden benches arranged in a semi-circular pattern. Numerous members of the assembly are seated, facing towards the center. The architecture features dark wood paneling and a high ceiling.

अचल संपत्ति की जानकारी देने से क्यों गुजें? वे कुछ छिपा रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। ऐसे में अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कोई दो मत नहीं कि ऐसे अधिकारी ही जवाबदेही से बचने का प्रयास करते हैं। जब ऊपरी स्तर पर जवाबदेही नहीं दिखेगी, तो निचले स्तर पर क्या उम्मीद की जा सकती है। यह तथ्य है कि ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना कहीं भी सुशासन की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर कोई अधिकारी आदेश के अनुपालन में लापरवाही भरता है, तो उसके खिलाफ निस्पत्तें करारवाइ होनी चाहिए। संसद की स्थायी समिति का यह सुझाव उचित है कि संपत्ति का ब्योरा दाखिल करने के लिए एक नियमानी तंत्र स्थापित हो और इसमें एक कार्यबल का गठन किया जाए, जो ब्योरा दाखिल न करने वाले अधिकारियों पर नजर रखें। इसके बाद आगे की प्रक्रिया तय होगी। सरकारी तंत्र में जवाबदेही सुनिश्चित होनी ही चाहिए। संसदीय समिति को इसी जवाबदेही की चिंता है। बेहतर होता कि बजाय कार्रवाई के डर से, अधिकारी स्वेच्छा से अपनी संपत्ति की सूचना देते। समिति की सिफारिश के बाद उम्मीद की जा सकती है कि इसके सकारात्मक नरीजे सामने आएं।





# શાદી સે ઇંકાર કિયા તો બંદુક કી નોક પર નાબાળિગ કા અપહરણ

સિવિલ લાઇન ક્ષેત્ર કે હિંગોનાખુર્ડ ગાવ મેં દેર રાત હુઈ ઘટના, મામલા દર્જ

-હિન્ડુસ્તાન એક્સપ્રેસ ન્યૂજ-

મુરૈના। દૂર યુદ્ધને કેવી બાબતોને સુધી પહેલે હુએ રિસેટે કેવી બાબતોને દૂર વધુ પદ્ધતિ કે લોણોને ને શાદી કરને સે ઇંકાર કર્યા તો કર એક કે લોણ હથિયારોને સે લેસ હોકર આથી રાત કો વધુ પદ્ધતિ કે ઘર આ થમકે. ઘર મેં મીજૂર્ડ પરિવાર કે લોણોનો બધાં બધાં ઔર ફાયરિંગ કરતે હુએ નાબાળિગ વધુ કોણ અગામ કર લે ગા. ઘટના સિવિલ લાઇન થાના ક્ષેત્ર કે અંતર્ગત હિંગોનાખુર્ડ પંચયત કે મજસા નાર વાળોનો પુરા મેં મંગલવાર કો રાત કરીબ સાથે 12 બજે હોના બતાઈ ગઈ હૈ.

મિલ્લો જાનકારી કે મુતાબિક રામાધાર સિંહ ગુર્જર નિવાસી નાર વાળોનો પુરા હિંગોનાખુર્ડ મંગલવાર કી રાત કો રાત મેં સો રહે થે. આથી રાત કરીબ સાથે 12 બજે લાખન ગુર્જર, શિવરાજ, જાપાન ગુર્જર, ભૂપેન્દ્ર ઉફ ટાઈપ, દેવન્દ્ર ઉફ નૈને નિવાસિણ કેમરા કેમરા થાના સરાયથીલ સહિત 5 બંદુક એવું 2 કંઠોને સે લેસ ડેડ ડર્જન લોણ રામાધાર ગુર્જર કે ઘર મેં બુસ આપા. હથિયારબંદ લોણોને ઘર કે અંદર સો રહે સીધી નિવાની કો બાદ સિવિલ લાઇન થાનાની કો પુલિસ મોકે પર હુંચી, લેકિન તવ તવ હમલાની નાબાળિગા શિવાની કો અગામ કર ભાગ ચુકે થે. પુલિસ ને પીડિત પણ એવું પણ આરોપી લાખન ગુર્જર, શિવરાજ, જાપાન ગુર્જર, ભૂપેન્દ્ર ઉફ ટાઈપ, દેવન્દ્ર ઉફ નૈને નિવાસિણ કેમરા કેવિલું એફઆઈઆર દર્જ કર લી હૈ.

(14) કો ઉઠાયા ઔર ફાયરિંગ કરતે હુએ ભાગ નિવાની કો બાદ સિવિલ લાઇન થાનાની કો પુલિસ મોકે પર હુંચી, લેકિન તવ તવ હમલાની નાબાળિગા શિવાની કો અગામ કર ભાગ ચુકે થે. પુલિસ ને પીડિત પણ એવું પણ આરોપી લાખન ગુર્જર, શિવરાજ, જાપાન ગુર્જર, ભૂપેન્દ્ર ઉફ ટાઈપ, દેવન્દ્ર ઉફ નૈને નિવાસિણ કેમરા કેવિલું એફઆઈઆર દર્જ કર લી હૈ.

લોણોનો બંદુક કી નોક પર બધાં બના લિયા। જિસને બાદ ઉન્હોને રામાધાર કી પુરી શિવાની ગુર્જર ને શાદી કરને સે ઇંકાર કર્યા તો કર એક કે લોણ હથિયારોને સે લેસ હોકર આથી રાત કો વધુ પદ્ધતિ કે ઘર આ થમકે. ઘર મેં મીજૂર્ડ પરિવાર કે લોણોનો બધાં બધાં ઔર ફાયરિંગ કરતે હુએ નાબાળિગ વધુ કોણ અગામ કર લે ગા. ઘટના સિવિલ લાઇન થાના ક્ષેત્ર કે અંતર્ગત હિંગોનાખુર્ડ પંચયત કે મજસા નાર વાળોનો પુરા મેં મંગલવાર કો રાત કરીબ સાથે 12 બજે હોના બતાઈ ગઈ હૈ.

સિવિલ લાઇન ક્ષેત્ર કે હિંગોનાખુર્ડ ગાવ મેં દેર રાત હુઈ ઘટના, મામલા દર્જ

## અમબાહ પુલિસ ને હત્યા કે પ્રયાસ સંબંધી પ્રકરણ મેં ફરાર ચલ રહે આરોપી કો દ્વાચા

-હિન્ડુસ્તાન એક્સપ્રેસ ન્યૂજ-

રખતે હુએ પુલિસ અધીક્ષક મુરૈના સમીક્ષા

થાના સ્તર પર ટીમ કા ગઠન કિયા ગયા

સારેખ (ભાસુસે) દ્વારા હત્યા કે પ્રયાસ

એવાં થાના પ્રભારી અમબાહ કો આવશ્ક

સારેખ સાથી કે લોણ કે વધુ પદ્ધતિ કે દિનાં

અતિઃસ્તાન એવાં અતિઃસ્તાન



15/04/2025 થારા 125,

296, 351(2), 3(5)

બી.એન.એસ. 3(1) દ, 3

(1) એસ્પેસસ્ટાટી એક્ટ

કા પંજીયદ્ધ કર વિવેચના મેં લિયા ગયા। પ્રકરણ કો

વિવેચના કે દેરાન સાથીય કે

આથાર પર પ્રકરણ મેં થાયા

109 બી.એન.એસ. કા જીજાના કે લિયા ગયા।

સંબંધી ઉક્કે પ્રકરણ મેં ફરાર

અરોપીની કો ગેરીઝેરી હેઠું

અરોપીની કો ગેરીઝેરી

